भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2388

सोमवार, 1 अगस्त, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

अता.प्र.सं. 2388 : डॉ. उदित राजः

श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करने की नीति अनुचित लाभ ले रही तथा पिछली नीति मानदंडों का उल्लंघन कर रही भारतीय ई-वाणिज्य कंपनियों को रोकेगी क्योंकि सरकार बहु-ब्रांड खुदरा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार इस नीति से लघु तथा मध्यम उद्यमों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करेगी;

(ग) क्या नए दिशानिदेश आनलाइन तथा आफलाइन खुदरा व्यापारियों के बीच विवाद को विराम देंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान बी2बी क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने का अनुमान है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): जहां तक ई-कॉमर्स क्षेत्र संबंधी एफडीआई नीति का संबंध है, दिनांक 14.07.2000 के प्रेस नोट 7(2000) के द्वारा अधिसूचित बी2बी क्रियाकलापों में वर्ष 2000 से स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। सरकार ने हाल ही में यह स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि ई-कॉमर्स का बाजार-स्थान मॉडल बी2बी ई-कॉमर्स के समान है।

बी2सी ई-कॉमर्स क्रियाकलापों में एफडीआई की अनुमति केवल पारंपरिक स्टोरों के माध्यम से कार्य कर रही एकल ब्रांड खुदरा व्यापार कंपनी, भारत में विनिर्मित और/अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार कंपनी और भारत में विनिर्मित सामानों के विनिर्माता के लिए है।

इस प्रकार, बी2सी ई-कॉमर्स क्रियाकलापों में उपयुक्त रूप से एफडीआई की अनुमति देने सहित ई-कॉमर्स के लिए उपर्युक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों से अन्य बातों के साथ-साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र संबंधी एफडीआई नीति में स्पष्टता आएगी और ई-कॉमर्स कंपनियों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित ऑफलाइन खुदरा व्यापारियों के बीच एक समान अवसर सृजित होंगे।

(घ): किसी क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाहों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एफडीआई मुख्य रूप से निजी व्यावसायिक निर्णयों का मामला है। एफडीआई अंतर्वाह कई कारकों जैसे कि प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, बाजार का आकार, अवसंरचना, राजनीतिक और सामान्य निवेश वातावरण के साथ-साथ वृहत-आर्थिक स्थायित्व और विदेशी निवेशकों के निवेश निर्णय पर निर्भर करते हैं।

*****